



भाजपा के तीन दिन के मंथन का परिणाम है सुरेश कश्यप और रणधीर शर्मा के ब्यान

शिमला/शैल। जयराम सरकार उपचुनाव में चारों सीटें हार गयी है। यह हार तब हुई है जबकि प्रदेश और केंद्र दो जगह भाजपा की सरकारें हैं। तीन विधानसभा और एक लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हुए। ऐसे में चारों सीटों पर हार का अर्थ है कि लोग प्रदेश और केंद्र दोनों ही सरकारों से खफा हैं। इस हार के कारणों को चिन्हित करने के लिए शिमला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। तीन दिन की इस बैठक में पहले दो दिन तो कोर



विश्वास बना। कल तक तो कांग्रेस को हर भाजपाई नेता विहीन पार्टी करार दे रहा था। यदि नेता विहीन होते हुए भी कांग्रेस जयराम सरकार से चारों सीटें छीन ले गयी तो अब आगे क्या होगा। स्वर्गीय वीरभद्र के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर की पूरी पिक्चर तो आम चुनाव में सामने आयेगी। इस मंथन में भले ही भाजपा नेतृत्व ने अपने ही नेताओं के उन बयानों का संज्ञान लिया हो जिनमें यह कहा गया था कि आगे ठेकों के काम उसी को



- ❖ सुरेश कश्यप ने अतिविश्वास और सहानुभूति को हार का कारण बताया
- ❖ रणधीर शर्मा ने कहा भीतरघात से हुई हार
- ❖ कृपाल परमार और पवन गुप्ता के त्याग पत्रों का जिक्र तक नहीं हुआ



कमेटी और उसकी विस्तारित बैठक ने ही ले लिये। दो दिन की कोर कमेटी में जो कुछ पका उसे तीसरे दिन कार्यकारिणी को परोसा गया। कोर कमेटी की दूसरे दिन की बैठक के बाद मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रैस को संबोधित किया और कहा कि भीतरघात के कारण हार हुई तथा इन भीतरघातियों के खिलाफ कारवाई की जायेगी। मुख्य प्रवक्ता के इस ब्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भीतरघातियों को चिन्हित कर लिया गया था। लेकिन तीसरे दिन की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने लंच पर मीडिया को संबोधित किया। सुरेश कश्यप ने भाजपा नेताओं के अति विश्वास और कांग्रेस के 6 बार रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के प्रति उपजी सहानुभूति की लहर को अपनी हार तथा कांग्रेस की जीत का कारण बताया। सुरेश कश्यप ने भीतरघात

का जिक्र तक नहीं किया। यहां यह उल्लेखनीय हो जाता है कि इस मंथन बैठक से ठीक पहले पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह त्यागपत्र देने के साथ ही परमार का जो पत्र सोशल मीडिया में सामने आया उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वह चार वर्षों से लगातार जलालत का सामना कर करते आ रहे हैं। कृपाल परमार ने यह भी कहा कि उन्होंने इस संबंध हर स्तर पर बात करके देख लिया और अब त्यागपत्र देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा है। कृपाल परमार के बाद प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सिरमौर के प्रभारी पवन गुप्ता का त्यागपत्र सामने आया। पवन गुप्ता ने तो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बघाट सरकारी बैंक

का संदर्भ उठाते हुये गुप्ता ने पूरी बेबाकी से यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा एक अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के नाम से भारी कर्ज ले रखा है।

इन त्याग पत्रों को प्रदेश प्रभारी ने यह कहकर हल्का बताने का प्रयास किया कि यह त्यागपत्र अभी सोशल मीडिया में ही चर्चा में है। जब उनके पास आयेगे तब उस पर चर्चा करेंगे। इसी तर्ज को दोहराते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी अपने आभासी संबोधन में इन त्यागपत्रों का उल्लेख तक नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सभी की यह राजनीतिक मजबूरी है कि वह त्यागपत्रों के कड़वे घूंट को चुपचाप निगल जायें। लेकिन यह त्यागपत्र और इनमें उठे मुद्दे पर देश की जनता के संज्ञान में आ चुके हैं क्योंकि यह सब लंबे

अरसे से संगठन और सरकार में घटता आ रहा है। एक समय इन्दु गोस्वामी ने भी अपने पद से त्यागपत्र देते हुये यही सब कुछ कहा है। भले ही संगठन सरकार और मीडिया के कुछ हल्के इस सबको नजरअंदाज कर दे लेकिन प्रदेश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और उसका प्रमाण चार शून्य के परिणाम में सामने की भी आ चुका है। इसी मंथन बैठक में मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष के भीतरघातियों को लेकर अलग-अलग बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है की इन त्यागपत्रों ने जयराम से लेकर नड्डा तक सभी की नींद हराम कर दी है।

सुरेश कश्यप जब भाजपाइयों के अति विश्वास को हार का कारण मान रहे हैं तब उन्हें यह बताना होगा कि जयराम सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धियां जिनसे अति

मिलेगे जिन की सिफारिश पार्टी के प्रत्याशी से आयेगी। यह भी कहा गया था कि यदि हमारा कुत्ता भी पड़ोसी के घर चला जाये तो हम उसे भी घर वापस नहीं आने देते हैं। इन बयानों के वीडियो चुनावों में खूब चर्चित रहे हैं। क्या ऐसे बयानों से पार्टी की छवि निखरेगी या यह सामने आयेगा कि अब सत्ता का नशा दिमाग तक चढ़ चुका है। इस मंथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों तक प्रदेश में न तो सरकार और न ही संगठन के स्तर पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होगा। जो भी घटेगा वह यूपी के परिणामों के बाद ही घटेगा। इसका प्रमाण त्यागपत्रों पर अपनाई गयी स्वामोशी से सामने आ चुका है। इसी दौरान यह भी सामने आ जायेगा की मुख्यमंत्री की कार्यशैली में क्या अंतर आता है।

स्वस्थ जीवन के लिए जीवनशैली में बदलाव आवश्यक: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए आज जीवनशैली में बदलाव आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में बहुत से गंभीर रोग जीवन शैली की विकृति के कारण हो रहे हैं, जिनसे सही जीवनशैली व खान-पान

निर्माण होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन से अवगत हो सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने ऐसे अनेक पौधे प्रदान किए हैं, जिनकी उपचार में उपयोगिता होती है। औषधीय पौधों की वाटिकाओं से आने वाली पीढ़ी को इन पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी

लिए भी सभी को प्रयास करने चाहिए क्योंकि यह देश को भविष्य का सवाल है तथा देश का भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है।

राज्यपाल ने कहा कि बीमारी के इलाज से अधिक बचाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में आयुर्वेद व योग के प्रति रूचि बढ़ी है।

कार्यक्रम में आरोग्य भारती संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश पंडित ने आरोग्य भारती संस्था के कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बेहतर बनाना ही आरोग्य भारती के गठन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी जैसी सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ लाकर एक नम्र चिकित्सा प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य को आवश्यकतानुसार उपचार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक नीति आयोग के माध्यम से नया हेल्थकेयर सिस्टम लाने के लिए प्रयास कर रही है, जिस पर बढ़-चढ़ कर कार्य किया जा रहा है।

इससे पूर्व आरोग्य भारती अध्यक्ष ऊना डॉ. रितेश सोनी ने राज्यपाल का

कार्यक्रम में स्वागत किया। प्रांत अधिवेशन में विभिन्न चिकित्सा पद्धति पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने अग्निहोत्र यज्ञ के साथ की। इस अवसर पर राज्यपाल ने पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज की

प्रोफेसर डॉ. सोनी कपिल की किताब आयुर्वेद प्रसूति तंत्र का विमोचन भी किया।

छठे राज्य वित्तयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ.अमित कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने थाना कलां गौशाला में किया गौ पूजन

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला ऊना के थाना कलां गौशाला में तुलसी अनुष्ठान व गौ पूजन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि,

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक गौ अभ्यारण्य तथा बड़ी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे सड़कों पर बेसहारा पशु नहीं होंगे तथा किसानों की फसलों को भी बेसहारा पशुओं से



मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी उपस्थित थे।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा गौवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग चार वर्षों में बीस हजार से अधिक बेसहारा गौवंश को सहारा प्रदान किया है।

कोई हानि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा गौशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। जून 2022 तक प्रदेश की राज्य की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर हमीरपुर के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला परिषद ऊना के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती के उत्पादों की सर्टिफिकेशन कर अलग पहचान दिलाने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और कृषि लागत घटने के साथ ही उत्पादन में

ने प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात कही।

उन्होंने प्राकृतिक खेती

भी मुलाकात की।

लाभार्थी जोगिन्दर पाल ने बताया कि उन्हें प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 57 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है तथा उन्होंने देसी गाय के गोबर व गौमूत्र का उपयोग कर रसायन मुक्त खेती को अपनाया है। सुख देवी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 75 वर्षीय कृष्णा देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें कूल्हे में चोट लगी थी तथा 25 हजार रुपए से उनका उपचार किया गया, जिसका पूरा व्यय प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत वहन किया, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की आभारी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी अप्पर नारी निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत उन्हें मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, नगर परिषद ऊना की अध्यक्ष पुष्पा देवी, उपायुक्त राघव शर्मा व एसपी अर्जित सेन ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



भी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के उत्पादों की सर्टिफिकेशन पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है तथा हिमाचल प्रदेश में भी इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं।

ऊना जिला के अपने तीन दिवसीय प्रवास के पहले दिन राज्यपाल

खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी लोअर बसाल निवासी जोगिन्दर पाल से उनके खेत में जाकर अनुभव सुने। गलुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की लाभार्थी सुख देवी का घर भी देखा और उनसे बात-चीत की। इसके उपरान्त अप्पर बसाल में हिमकेयर योजना की लाभार्थी कृष्णा देवी से तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी अप्पर नारी निवासी सुरेंद्र कुमार से

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT					

Online INVITATION FOR BIDS (IFB)					
The Executive Engineer, Salooni Division, HPPWD Salooni-176320 H.P. on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites the items rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.					
Sr.No.	Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money (In Rs.)	Deadline for submission of Bid
1.	Construction of link road from Bihali Bachuni Chamber Katara road K.M. 4/600 to 11/100 in Tehsil Salooni District Chamba HP (SH: Construction of 2 Nos hume pipe culvert alongwith wing walls, Breast wall and Retaining wall at various R.Ds) (Under BASP)	45,77,223/-	08-12-2021	91,600/-	15-12-2021 90 Days D & up to 11.00 A.M. C
2.	Construction of Rain Shelter at Malal on Lachori to Seri road at K.M. 3/700.	74,120/-	08-12-2021	2,000/-	15-12-2021 120 Days D & up to 11.00 A.M. C
3.	Construction of Rain Shelter at Andral on Lachori to Seri road at K.M. 5/810.	74,120/-	08-12-2021	2,000/-	15-12-2021 120 Days D & up to 11.00 A.M. C
The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in. The Date of Technical bid opening: 15-12-2021 11.30 A.M.					
Adv. No. 5236/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK					

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

शहरी विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी शहरी विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर राज्य के लोगों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है।

इस उपलब्धि पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग ने देश के 56 शहरों को इसमें शामिल किया था, जिनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाली 12 राज्यों की राजधानियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि यह सूची गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, सस्ती और सुलभ ऊर्जा

और जलवायु जैसे मापदण्डों के तहत शहरों के प्रदर्शन को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस सूची के मूल्यांकन के लिए 46 लक्ष्य और 77 संकेतक निर्धारित किए गए थे और शिमला शहर को 100 में से 75.50 अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों में वास करती है, परन्तु देश के विकास में शहर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नीति आयोग ने इंडो-जर्मन विकास निगम के अन्तर्गत जीआईजैड और बीएमजैड के सहयोग से सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक से संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए एक डैश बोर्ड विकसित किया है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT					
e-Procurement Notice					
INVITATION FOR BIDS (IFB)					
1.The Executive Engineer HPPWD Jubbal Distt Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.					
Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of Tender	Time Eligible Class of Contractor
1.	Restoration of rain damages on Kharapather Patsari RAO D Km 0/0 to 13/120 Km (SH:-Extra layer for surface coection at various damaged portions between Km 1/00 to 3/500)	Rs.949957/-	Rs.19000/-	Rs.500/-	1 Month Class D
2	Restoration of rain damages on Kharapather Patsari Km 0/0 to 11/500 (SH:-Extra layer for surface coection at various damaged portions between Km 3/500 to 6/0)	Rs.949957/-	Rs.19000/-	Rs.500/-	1 Month Class D
3.	Restoration of rain damages on Mandhole Mangauta RAO D Km 0/0 to 8/645 (SH:-Extra layer for surface coection at various damaged portions between Km 0/0 to 4/0)	Rs.960637/-	Rs.19300/-	Rs.500/-	1 Month Class D
4.	Restoration of rain damages on Mandhole Mangauta RAO under Km 0/0 to 8/645 (SH :- Extra layer for surface coection at various damaged portions between Km 4/0 to 8/645)	Rs.981676/-	Rs.19800/-	Rs.500/-	1 Month Class D
Tender document and other instructions can be downloaded or viewed online from the portal https://hptenders.gov.in by the firm/individual registered on the website which is free of cost.					
Key Dates:					
1.	Date of Online Publication	02.12.2021 11:00 HRS			
2.	Document Download Start and End Date	02.12.2021 1130 HRS upto 08.12.2021 1730 HRS			
3.	Bid Submission Start and End Date	02.12.2021 1130 HRS upto 08.12.2021 1800 HRS			
4.	Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	09-12-2021 1100 Hrs			
5.	Date of Technical Bid opening.	09.12.2021 1130 HRS			
6.	Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	Date to be announced			
Adv. No. 5152/21-22		HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK			

प्रदेश सरकार हिमाचल में फिल्म उद्योग को वन निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को छह प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का निर्णय आकर्षित करने के लिए प्रयासरत: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अन्तरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, शिमला के पुरस्कार समारोह

है लेकिन हिमाचल प्रदेश अपना फिल्म उद्योग विकसित नहीं कर पाया। उन्होंने आशा जताई कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल

निर्माताओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने इस अवसर पर श्रेष्ठ फिल्मों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्र को पुरस्कार भी प्रदान किए।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर भारतीय सिनेमा के आरम्भ से फिल्म निर्माताओं की प्रथम पसंद है। भारतीय सिनेमा देश के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को सुदृढ़ करने के लिए श्रेष्ठ विकल्पों में से एक है।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉ. पंकज ललित ने कहा कि इस तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान 16 देशों की फिल्मों प्रदर्शित की जाएगी।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विजय ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए हिमाचल प्रदेश हमेशा ही पसंदीदा गंतव्य रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण फिल्म उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा था और अब सिनेमा जगत ने पुनः कार्य आरम्भ कर दिया है। भारतीय सिनेमा अब पुनः गतिविधियों का केन्द्र बन रहा है।

7वें शिमला अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के फेस्टिवल निर्देशक पुष्प राज ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि तीन दिवसीय फेस्टिवल के दौरान अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की 58 फिल्मों प्रदर्शित की गईं, जिसमें से 6 फिल्मों हिमाचल प्रदेश से थीं।

नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौडल, सचिव भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी डॉ. कर्म सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला/शैल। राज्य वन विकास निगम के निदेशक मण्डल की 210वीं बैठक का आयोजन होटल होलीडे होम में वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर राकेश पठानिया ने कहा कि वन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के

मंहगाई भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि वन निगम ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति नियमित करने का निर्णय भी बैठक में लिया। वन निगम की बिरोजा एवं तारपीन फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को दीवाली उपहार की



लिए बोनस दिया गया। बैठक में वन निगम में कार्यरत दैनिकभोगी और अंशकालीन कार्यकर्ताओं को सरकार की नीति के अनुसार वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त वन निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रथम जुलाई, 2021 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति छह प्रतिशत

राशि भी बढ़ाई गई।

बैठक में उपाध्यक्ष वन निगम सूरत सिंह नेगी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) अजय श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक राजीव कुमार, कार्यकारी निदेशक आर. लालननुसांगा, निदेशक विनय कुमार, राम कुमार, डी.एस. ठाकुर, बलविन्द कुमार, जगदेव सिंह सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संविधान दिवस डा.भीमराव अम्बेडकर के समक्ष सम्मान प्रकट करने का अवसर है: सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास और विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के समक्ष सम्मान प्रकट करने का अवसर है।

उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार को साझा किया कि संविधान मात्र वकीलों का एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का पहिया है और इसकी आत्मा हमेशा से युग की आत्मा है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह दिन संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों पर हमारे विश्वास को पुनः पुष्टि करने का दिन है। संविधान के माध्यम से हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी।

उन्होंने लोगों को देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहने का आग्रह

किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केन्द्र सरकार भारत के संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने 26 जून, 1975 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय संविधान के महत्त्व को कम करने के प्रयास के तहत प्रेस को नियंत्रण किया गया था और लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने भी सरकार के अत्याचारों का सामना किया था पर यह संविधान की ताकत ही थी कि देश की जनता ने अहंकारी शासकों को सत्ता से बाहर किया था।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार और कर्तव्य हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तम्भ हैं जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन बनाए रखते हैं।

प्रदेश में वाहनों के निरीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया

शिमला/शैल। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में 24 से 26 नवम्बर, 2021 तक वाहनों के निरीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी बसों में यात्री टिकट जारी करना सुनिश्चित करवाया गया। इसके अतिरिक्त क्षमता से अधिक भरे गए मालवाहक वाहनों को मोटर वाहन नियमों के अनुसार ही वाहन में सामान लोड करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान 145 गाड़ियों के चालान कर 3,69,500 रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूल की गई। उन्होंने कहा कि निदेशक परिवहन की ओर से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को भविष्य में भी इसी प्रकार के औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा सभी वाहन मालिकों से मोटर वाहन नियम/अधिनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।



को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भाषा, कला एवं संस्कृति के संरक्षण पर निरन्तर बल दे रही है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिल्मों श्रेष्ठ विकल्पों में एक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी फिल्म नीति तैयार की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन तैयार किया है ताकि फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। फिल्म सिटी की स्थापना से देश व विश्व के फिल्म निर्माता प्रदेश में ही पूरी फिल्म की शूटिंग तथा निर्माण कर सकेंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के खूबसूरत स्थानों तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के फलस्वरूप देश तथा विदेश के अनेक फिल्म निर्माताओं ने हिमाचल प्रदेश में अपनी फिल्मों की शूटिंग की

प्रदेश के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने में अवश्य प्रेरित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित सकारात्मक वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे आयोजनों को आयोजित करने के लिए सम्पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि फिल्म फेस्टिवल के दौरान मॉडल सेन्ट्रल जेल कंड़ा के बंदियों के लिए भी एक विशेष फिल्म प्रदर्शित की गई।

जय राम ठाकुर ने फिल्म फेस्टिवल के प्रतिभागियों, आयोजक हिमालयन विलोसिटी, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, फिल्म निर्देशकों, निर्माताओं तथा कलाकारों को अन्तरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के सातवें संस्करण को सफल बनाने के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए

हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा अधिकारी संघ का स्वर्ण जयंती समारोह

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा (एचपीएफए एंड एएस) ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित

अधिकारी विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान



किया। इस अवसर पर सचिव वित्त एवं योजना अक्षय सूद, विशेष सचिव वित्त राकेश कंवर और निदेशक कोष लेखा एवं लॉटरी विभाग अमरजीत सिंह भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य के विकास और प्रगति में इस सेवा के अधिकारियों के योगदान और विशेष रूप से संबंधित विभागों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्त एवं लेखा सेवा के

करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से और दृढ़ता और समर्पण भाव से कार्य करने का आग्रह किया।

वित्त और लेखा सेवाएं वर्ष 1971 में अस्तित्व में आईं और राज्य में अपनी सेवाओं के योगदान के माध्यम से अपनी शानदार यात्रा के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए।

संघ के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य

सचिव ने वित्त एवं लेखा सेवा के वर्ष 2020-2021 के सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों संवर्ग में सेवा करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए।

स्वर्ण जयंती समारोह के बाद एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी चुनी गई। राजेश शर्मा नियंत्रक को अध्यक्ष, श्रवण कुमार नेगी उप नियंत्रक को मुख्य सलाहकार, बलबीर कुमार उप नियंत्रक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश कुमार सिंह उप नियंत्रक को उपाध्यक्ष मुख्यालय, प्रवीण शर्मा उप नियंत्रक को उपाध्यक्ष (क्षेत्र), भारत भूषण, सहायक नियंत्रक को महासचिव, कर्म चंद वर्मा सहायक नियंत्रक को संयुक्त सचिव-1, नरेश कुमार सहायक नियंत्रक को संयुक्त सचिव-2, विनोद कुमार गौतम अनुभाग अधिकारी को कोषाध्यक्ष, राकेश वर्मा अनुभाग अधिकारी को सहायक कोषाध्यक्ष, प्रणव नेगी सहायक नियंत्रक को आयोजन सचिव, संदीप शर्मा सहायक नियंत्रक को प्रेस सचिव, रमन कुमार सांजटा अनुभाग अधिकारी को कार्यकारी सदस्य और विनोद शर्मा अनुभाग अधिकारी को कार्यकारी सदस्य चुना गया।

प्रकृति (सहज) रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

कृषि कानूनों की वापसी से उठते सवाल



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के साथ ही यह चर्चा चल उठी है कि क्या यह कानून उत्तर प्रदेश में संभावित हार के डर से वापस लिए गये हैं या इमानदारी से प्रधानमंत्री ने उसे गलत फैसला मान कर यह कदम उठाया है। यह दोनों ही बिन्दु महत्वपूर्ण हैं और देश की आगामी राजनीति पर इनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन दोनों ही बिन्दुओं की निष्पक्ष विवेचना करना आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करते हुए देश से क्षमा याचना भी की है। लेकिन यह क्षमा याचना इसके लिए की गई है कि वह

इन कानूनों का लाभ किसानों को समझाने में असफल रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि वह अभी भी यह नहीं मानते कि यह कानून लाना एक गलत फैसला था। शायद इसी कारण से एक भाजपा नेता के उस ब्यान का कोई खंडन नहीं किया गया जिसमें कहा गया है कि इन कानूनों को वापस लाया जायेगा। प्रधानमंत्री की कानून वापसी की घोषणा पर उन उद्योग घरानों की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है जिनके दबाव में यह कानून लाने का आरोप लगाया जा रहा था। फिर 700 किसानों की मौत के बाद आये इस ऐलान में उन किसानों की शहादत पर दो शब्द भी न आना इसकी पुष्टि करता है कि इस कदम के पीछे भी कोई रणनीति अवश्य है।

अगले वर्ष के शुरू में ही पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यह एक स्थापित सत्य है। बंगाल की हार के बाद हुये कुछ राज्यों के उपचुनावों में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस हार से प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि पर असर पड़ा है। अब यह धारणा निर्मूल साबित हो चुकी है कि “मोदी है तो मुमकिन है”। जो लोग मोदी को शिव और विष्णु का रूप मानने लग गये थे आज इस हार ने उनको नैतिकता का संकट खड़ा कर दिया है। इस परिपेक्ष में वस्तुस्थिति का आकलन करते हुये यही मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की संभावित हार के परिदृश्य में ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया गया है। ऐसे में इस समय 2014 से लेकर अब तक लिये गये हर आर्थिक फैसले को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। क्योंकि उन्हीं फैसलों के कारण आज बैंकों का एनपीए ढाई लाख करोड़ से 10 ट्रिलियन करोड़ तक पहुंच चुका है। इस एनपीए के कारण पेट्रोल और डीजल तथा खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ी थी। अब जब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करनी पड़ी है तो जीएसटी की दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत कर दी गयी। यह स्पष्ट है कि सरकार एनपीए की रिकवरी करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें सबसे अधिक योगदान प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में बाटे गये कर्ज का है। एनपीए का असर आने वाले दिनों में हर आदमी पर दिखेगा। चाहे वह भाजपा मोदी का समर्थक हो या विरोधी जब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामने आयेगा उस समय जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता हो जाता है। महंगाई बेरोजगारी और अयोध्या में राम मंदिर के लिये हुई जमीन खरीद में सामने घपलों ने निश्चित रूप से भाजपा की राजनीतिक जमीन को बेहद कमजोर कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये यह चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति ही शायद अंतिम हथियार मोदी शाह के हाथ में बचा है। क्योंकि किसानों ने इस ऐलान के बाद भी अपना आंदोलन वापिस नहीं लिया है। एमएससी के प्रावधान की वैधानिक मांग उतना ही बड़ा हथियार बन गया है। अभी सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल में जिस तरह से बढ़ोतरी की गयी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष निशाने पर है। विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और 2014 से आज तक सरकार का मुकाबला कर रहा है। अभी तक किसी भी नेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। कांग्रेस ही हर मुद्दे पर सरकार का खुलकर विरोध करती आयी है। अब बंगाल परिणामों के बाद टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व ईडी के निशाने पर आया है। सपा बसपा पहले से निशाने पर चल रहे हैं। इसलिये यह दल अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना पाये हैं। आप और टीएमसी भी 2024 के चुनावों तक राष्ट्रीय विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है। इस समय मोदी और भाजपा को कोई चुनौती है तो वह केवल कांग्रेस से है। इसलिए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा की परोक्ष/अपरोक्ष में यह रणनीति रहेगी कि वह टीएमसी आप और सपा-बसपा को ताकत दे। इसके लिए कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को इन दलों में धकेलने का प्रयास होगा ही। इस समय जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने को इसी परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है।

आज जिस आर्थिक स्थिति पर देश पहुंच चुका है उसके लिए वर्तमान सरकार के फैसले ही जिम्मेदार हैं। इन फैसलों को पलटने के लिए वर्तमान सत्ता जैसी ताकत ही केंद्र में चाहिये। क्योंकि आज अगर सरकार के आर्थिक फैसलों के कारण आम आदमी कमजोर न हुआ होता तो शायद लोगों का भाजपा और मोदी से मोहभंग न होता। आर्थिक फैसलों के कुप्रभावों को हिन्दू-मुस्लिम, राम मंदिर गौरक्षा, धारा 370 और तीन तलाक के नाम पर जो दबाने के प्रयास किये गये आज वह सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। इस समय सैकड़ों विदेशी कंपनियों एफडीआई के नाम पर देश की आर्थिकी पर कब्जा कर चुकी है। इस सबके परिणाम आने वाले दिनों में क्या रंग दिखायेंगे यह तो आगे ही पता चलेगा। इसलिये इस समय राजनीतिक चयन दलों से ज्यादा की समझ भी कसौटी होगा।

बांग्लादेशी नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान कर भारत ने आपसी संबंधों को नए ढंग से परिभाषित किया



गौतम चौधरी

दुनिया को पता है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक अपने ही देश पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर जुल्म करने लगे तो भारत ने उसका जम कर विरोध किया। उस दौर में बांग्लादेश की हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और लाखों नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय बांग्लादेश के नागरिकों को भारत सरकार ने सरकारी तौर पर और भारत की जनता ने सामाजिक तौर पर सहायता प्रदान की। उसी समय से भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री विकसित हुई वह दिन व दिन मजबूत होती जा रही है। हालांकि बीच के समय में कुछ दिनों के लिए पाकिस्तानी षड्यंत्र से पनपी साम्प्रदायिक शक्तियों के कारण बांग्लादेश भारत विरोधी खेमे में शामिल हो गया था लेकिन वहां की जनता ने हर मोड़ पर भारत को अपना माना। अब बांग्लादेश में बंगबंदु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की सरकार है और बांग्लादेश न केवल भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा है, अपितु अपनी जमीन को भारत के खिलाफ उपयोग करने वाली शक्तियों पर जबरदस्त आक्रमण भी कर रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश दिन व दिन विकास के नित नवीन लक्ष्य को प्राप्त करता जा रहा है।

6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश संप्रभुता संपन्न एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उपस्थित हुआ। आजादी के तुरंत बाद बांग्लादेश को भारत ने सबसे पहले मान्यता प्रदान की। वर्तमान वर्ष को दोनों देश, बांग्लादेश की मुक्ति और भारत के साथ उसके राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक संबंध उनके साझा इतिहास और भौगोलिक निकटता का परिणाम हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई प्रकार की असहमति है और कूटनीतिक मामले अनसुलझे भी हैं।

इधर के दिनों में भारत-बांग्लादेश के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है। उस घटना के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती की कड़ी और मजबूत हो गयी है। इससे सामाजिक संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत-बांग्लादेश मैत्री की 50वीं वर्षगांठ पर भारत और बांग्लादेश के हित में काम और योगदान को लेकर बांग्लादेश के दो नागरिकों को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाएगा।

भारत सरकार ने इस वर्ष सैयद मुअज्जम अली को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म भूषण से नवाजा है। इसके अलावा इनामुल हक को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन दोनों सम्मानों से बांग्लादेशी समाज का भारत के प्रति झुकाव बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। यह आगे दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं से प्रभावित संबंधों को सुधारने में भारत की रुचि को इंगित करता है।

यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि विगत कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में साम्प्रदायिक शक्तियों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के त्रिपुरा में भी हल्की घटनाएं घटी लेकिन भारत सरकार की सूझ-बूझ ने दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो रहे गतिरोध को समाप्त कर दिया। उस पर यह नागरिक सम्मान दोनों देशों के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ बना दिया है।

वैसे बांग्लादेश में बहुसंख्यकवादी हिंसा की बार-बार होने वाली घटनाओं का असर भारत पर भी पड़ता रहा है। उसी प्रकार भारत में होने वाली अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की तेज और व्यापक असर बांग्लादेश पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश एक हिंदू मंदिर में मुस्लिम पवित्र

पुस्तक, कुरान के कथित अपमान को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बहुसंख्यकों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता, आगजनी और हमले किए। यह जल्द ही त्रिपुरा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का कारण बन गया। इस प्रकार की हिंसा हमारे कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। लेकिन सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास से समाज में कई प्रकार की सकारात्मकता देखी जा सकती है।

अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा पर बांग्लादेशी समाज ने जबर्दस्त प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आम नागरिकों ने रैलियां निकाली। कई नागरिक संगठनों ने हिंसा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में शांति मार्च का आयोजन किया। सरकार ने भी कार्रवाई की और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में शामिल अपराधियों को जेल भेजा गया। अवामी लीग के अधिकारी और ढाका विश्वविद्यालय के छात्र धार्मिक विभाजन के विकास के विरोध में एकजुट हुए। लोगों को लगा भड़काउ संदेश भेजने वालों को अगर नियंत्रित करना है तो एकमात्र तरीका नफरत के खिलाफ एकजुट होना है।

इन तमाम गतिरोधों के बावजूद भारत के द्वारा नागरिक सम्मान की पहल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम देने लगा है। यही नहीं इस सम्मान के बाद दोनों देशों के संबंधों को नए ढंग से परिभाषित किए जाने लगा है। भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच का संबंध सामाजिक आधार भी ग्रहण करे। हिंदू अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करके बांग्लादेश इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस सम्मान का लक्ष्य बांग्लादेश सरकार को मुस्लिम बहुसंख्यकों को सांप्रदायिक सद्भाव के लाभों से अवगत कराना है और साथ ही उन्हें अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना भी है। इसके अलावा, इसे समाज के उन तत्वों को न्याय के कटघरे में लाना है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं।

मिशन वन धन के तहत देश में 50,000 से अधिक वन धन स्वयं सहायता समूह स्वीकृत

शिमला। 'सबका साथ, सबका विकास' के लक्ष्य को साकार करने और संकल्प पत्र 2019 में किए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में, 'लोकल के लिए लोकल बनें, जनजातीय उत्पाद खरीदें' के नारे के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप, ट्राइफेड (संकल्प से सिद्धि-मिशन वन धन) को लागू कर रहा है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, मिशन वन धन का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 15 जून 2021 को किया गया था। इस मिशन ने 3,000 वन धन विकास केंद्र के क्लस्टरों (वीडीवीकेसी) में सम्मिलित 50,000 वन धन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की स्थापना का लक्ष्य रखा है। ट्राइफेड राज्यो के नोडल विभागों, राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों, भागीदारों, पिछले कुछ वर्षों में स्थापित किए गए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करते हुए विभिन्न भागीदारों के अपने इकोसिस्टम के माध्यम से इस योजना को व्यवस्थित और कुशलता से लागू करने के लिए सक्रिय है।

दो वर्षों की छोटी सी अवधि में, इसने सफलतापूर्वक 27 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के 9.27 लाख लाभार्थियों को कवर करने वाले 3110 वन धन विकास केंद्र क्लस्टरों (वीडीवीकेसी) में सम्मिलित 52,976 वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) को स्वीकृत किया है। ये वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (वीडीवीकेसी) विकास के विभिन्न चरणों में हैं और अब तक इनकी सफलता की कई कहानियां सामने आई हैं। महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में स्थित वन धन विकास केंद्र क्लस्टरों (वीडीवीकेसी) ने सभी 27 प्रतिभागी राज्यों के साथ-साथ लगभग 600 किस्मों के उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

इस सराहनीय उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए 29 नवंबर, 2021 को एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एसआईए एवं एसएनए के सदस्यों, जनजातीय लाभार्थियों और अन्य हितधारकों की उल्लेखनीय संख्या में भागीदारी देखी गई और ट्राइफेड के पेज वन धन से

विकास के माध्यम से लाइव स्ट्रीम की गई <https://www.facebook.com/VanDhanSeVikas/A>

यह एक उपयोगी सत्र रहा जिसमें इस योजना से जुड़ी समस्याओं और इसकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसमें ट्राइफेड के अध्यक्ष रामसिंह राठवा और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। ट्राइफेड जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए कई उल्लेखनीय पहलों को लागू कर रहा है। वास्तव में पिछले दो वर्षों में, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपजों (एमएफपी) के विपणन के तंत्र और लघु वनोपजों (एमएफपी) के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास' ने जनजातीय इकोसिस्टम को खासा प्रभावित किया है। वन धन शब्द प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2019 को बीजापुर, छत्तीसगढ़ में इस योजना का उद्घाटन करते समय गढ़ा गया था। इसी योजना के एक घटक के तौर पर, यह वन आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन का एक कार्यक्रम है। यह जनजातीय संग्रह कर्तियों और वनवासियों और घर में रहने वाले जनजातीय कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के एक स्रोत के रूप में उभरा है। 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 9.27 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3110 वीडीवीके क्लस्टरों में सम्मिलित 52,976 वन धन स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गयी है। इन समूहों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और आईआईटी, टीआईएसएस आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से 'जनजातीय लोगों के लिए तकनीक' (टेकफॉरट्राइबल) कार्यक्रम के माध्यम से 36,925 लाभार्थियों का उन्नत स्तर का प्रशिक्षण जारी है। सभी सक्रिय समूहों ने लघु वनोपजों (एमएफपी) की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें से लगभग 1600 समूहों ने मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनकी सफलता की कई कहानियां सामने आई हैं और 1500 लाख रुपये से अधिक की बिक्री हुई है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर (बस्तर) और महाराष्ट्र के

रायगढ़ में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की दो वृहद परियोजनाएं निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इस मिशन के तहत उद्यम का दृष्टिकोण बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था को संभव बनाएगा, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा और सभी मौजूदा निधियों एवं संसाधनों का लाभ उठाते हुए जनजातीय स्वामित्व वाली और जनजातीय लोगों द्वारा प्रबंधित उत्पादन इकाइयों का निर्माण करेगा।

इन सफलताओं और गतिविधियों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, जनजातीय लोगों की आजीविका के विकास और उद्यमों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने वाली एक पहल की परिकल्पना की गयी है। इन वीडोएसएचजी/वीडीवीकेसी को स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और कौशल के आधारित जनजातीय लोगों के स्थायी उद्यमों के रूप में पोषित और विकसित किया जाएगा।

इस मिशन की गतिविधियों को अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए देशभर में लागू किया जायेगा और यह वन धन कार्यक्रम एवं एमएफपी के लिए एमएसपी योजना के तहत सभी 27 राज्यों और 308 जनजातीय बहुल जिलों को कवर करते हुए निरंतर जारी रहने वाला एक कदम है। इस पहल से एक मिलियन जनजातीय परिवारों को सक्रिय रोजगार एवं आजीविका मिलने की उम्मीद है ताकि वे बिना किसी विस्थापन या प्रवास की जरूरत के वन संसाधनों और इससे जुड़ी गतिविधियों का लाभ उठाकर उन उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें जिनसे वे पहले से परिचित हैं।

जनजातीय लोगों के लिए साल भर आय पैदा करने के अवसर सुनिश्चित करने और बिना किसी अधिकार के भूमि/घर का कब्जा (लघु वनोपज के संग्रहण में प्रतिबंध (बिचौलियों द्वारा शोषण, विस्थापन, इस मिशन मोड में वन गांवों में विकास की कमी, आदि जैसे उनके सामने आने वाली विकट समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देने के साथ-साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के अगले चरण की शुरुआत किए जाने की उम्मीद है।

हिमालयी हिमनद के मार्ग में परिवर्तन से हिमानी और धरातल के पारस्परिक प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है

शिमला। भारत के पर्वतीय प्रांत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला स्थित ऊपरी काली गंगा घाटी क्षेत्र में एक अज्ञात ग्लेशियर अर्थात हिमनद का अध्ययन कर रहे भारतीय शोधकर्ताओं ने बताया है कि ग्लेशियर ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल दिया है। यह पहली बार है कि हिमालय के ग्लेशियर से इस तरह के मार्ग बदलने की सूचना मिली है, और शोधकर्ताओं ने इसके लिए जलवायु और विवर्तनिकी (टेक्टोनिक्स) अर्थात धरातल की रचना दोनों के संचित प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया है।

इस अज्ञात ग्लेशियर के असामान्य व्यवहार जाहिर है कि सिर्फ जलवायु एक निरोधक कारक नहीं है बल्कि टेक्टोनिक्स भी हिमनदों के जलग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में ऋषिगंगा में आयी आपदा एक ताजा उदाहरण है जो यह बताती है कि जिस चटान पर ग्लेशियर टिका हुआ था वह समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर हो गया (अपक्षय के कारण, संधि-स्थल में पिघले हुए पानी के रिसने से, दरारें पड़ने से, जमने व पिघलने, बर्फबारी व अधिक बोझ बढ़ने और धीरे-धीरे टेक्टोनिक बलों के काम करने से चटान के यांत्रिक रूप विघटित होने से) और अपने स्रोत से अलग हो गया। इससे साफ होता है कि हिमालय एक सक्रिय पर्वत श्रृंखला है और यह अत्यंत भंगुर भी है जिसके लिए टेक्टोनिक्स और जलवायु की अहम भूमिका होती है।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित अज्ञात हिमानी के मार्ग को अवरुद्ध करके उसे दक्षिण-पूर्व की तरह बढ़ने को बाध्य कर दिया गया था।

रिमोट सेंसिंग और एक पुराने

सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर किए गए अध्ययन यह अनुमान लगाया गया कि इस ग्लेशियर पर किसी सक्रिय विच्छेद और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। टेक्टोनिक गतिविधि और जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण इस ग्लेशियर का मार्ग और आकृति में परिवर्तन हुआ। सक्रिय भ्रंश के भ्रंश खड़ी ढाल बनी जो उत्तर में खाई से करीब 250 मीटर ऊँची है। भ्रंश अवशेष की लंबाई 6.2 मीटर है और इसका झुकाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ है। टेक्टोनिक रूप से गढ़ी गई विलक्षण ग्लेशियर के लैंडफॉर्म पर आधारित यह अध्ययन 'जियोसाइंस जर्नल' में प्रकाशित हुआ है।

डब्ल्यूआईएचजी की टीम ने पाया कि 5 किमी लंबे अज्ञात ग्लेशियर, जो कुठी यांकी घाटी (काली नदी की सहायक नदी) में करीब 4 किमी 2 क्षेत्र को फैला है, ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल लिया है। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा (19-24 केए) और होलोसीन के बीच के समय के दौरान टेक्टोनिक बल के काम करने के फलस्वरूप यह आगे चलकर मुड़ गया, और अंत में पास स्थित समजुर्कचाकी नामक में मिल गया। यह ग्लेशियर का एक अनूठा व्यवहार है और ग्लेशियर के गतिविज्ञान का ऐसा कोई प्रकार अब तक नहीं देखा गया।

अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि जलवायु ही एकमात्र कारक नहीं है जिसके चलते सक्रिय पर्वतीय श्रृंखला हिमालय में आपदाएं आती हैं, बल्कि ग्लेशियर के कैचमेंट में टेक्टोनिक्स की भी अहम भूमिका होती है। इससे ग्लेशियर अध्ययन के क्षेत्र में, खासतौर से ग्लेशियल-टेक्टोनिक अंतरक्रिया द्वारा गढ़ी गई भू-आकृतियों में बदलाव और उसकी उत्पत्ति पर केंद्रित एक नए नजरिये के लिए दरवाजे खुलते हैं।

मनरेगा में इस वर्ष 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया जा चुका है

शिमला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार द्वारा की गई मांग के विरुद्ध कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एक मांग प्रेरित स्कीम है।

अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के अनुसार 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया जा चुका है।

मजदूरी और सामग्री के लिए फंड जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। बजट आकलन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान फंड आवंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए

68,568 करोड़ रुपये से अधिक के फंड जारी किए जा चुके हैं।

जब भी, अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से फंड जारी किए जाने का अनुरोध किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, वित्त मंत्रालय ने बजट अनुमान के अतिरिक्त, इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान चरण के दौरान मांग के आकलन पर आवंटन किया जा सकता है।

भारत सरकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए लागू अधिनियम तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, स्कीम के समुचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी तथा सामग्री भुगतान के लिए फंड जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट छात्रवृत्ति योजना से आएका छात्रों की प्रतिमा में निखार

शिमला। राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा 12वीं कक्षा के पश्चात राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध करवाने हेतु मेधावी विद्यार्थियों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी क्रम में छोटी उम्र में प्रतिभा को चिन्हित कर उभारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए एक नई हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय

विद्यालय के छोटी से आठवीं कक्षा के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन एस.सी.ई.आर.टी. सोलन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को कक्षा छठी में चार हजार रुपये प्रतिमाह, कक्षा सातवीं में पांच हजार रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा आठवीं में छः हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में राज्य भर में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों को, विभिन्न जिलों की औसत छात्र के आधार पर जिलावार आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना के तहत जिला बिलासपुर के पांच लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिला चम्बा के 12 विद्यार्थियों,

जिला हमीरपुर के पांच विद्यार्थियों, जिला कांगड़ा के 14 विद्यार्थियों, जिला किन्नौर के एक विद्यार्थी, जिला कुल्लू के आठ विद्यार्थियों, जिला लाहौल-स्पीति के एक विद्यार्थी, जिला मंडी के 14 विद्यार्थियों, जिला ऊना के सात विद्यार्थियों तथा जिला शिमला, सिरमौर व सोलन प्रत्येक के 11-11 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चयनित विद्यार्थी को निरंतर तीन वर्षों तक कक्षा आठवीं तक सरकारी पाठशाला में ही अध्ययनरत रहना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संबंधित शैक्षणिक स्तर में उसे पाठशाला में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। केवल गंभीर चिकित्सीय कारणों की स्थिति में ही इस शर्त में छूट प्रदान की जाएगी।

हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा।

जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई, 2003 से नई पेंशन प्रणाली (इनवेलिड पेंशन और फैमिली पेंशन) के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण/दैनिक वेतनभोगी के रूप में रूपान्तरण के लिए भी एक-एक वर्ष की अवधि कम की जाएगी।

उन्होंने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति

❖ अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की घोषणा

बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति आगामी मंत्रिमण्डल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं



अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अब पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी

लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई, 2003 से 22 सितम्बर, 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेज्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कर्मचारियों की परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल आज देश के अन्य राज्यों के



लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या और कर्मचारी अनुपात के मामले में भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य इस संकट से सफलतापूर्वक

बाहर निकलने में सफल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छोटे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 22 प्रतिशत की वृद्धि की है और उन्हें 1320 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12 प्रतिशत अंतरिम राहत की दो किस्में भी प्रदान की गईं, जिससे कर्मचारियों को लगभग 740 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं कार्मिक प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा राज्य है।

राज्य एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि

राज्य के विकास में हिमुडा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा : सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के कार्य और वित्तीय स्थिति में सुधार की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को सभी सम्बन्धित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में हिमुडा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और प्रदेश सरकार इसके कार्यों को गति प्रदान के लिए प्रयासरत है।

हिमुडा के अधिकारियों ने उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में शहरी एवं आवास मंत्री को सिफारिशों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया। शहरी विकास मंत्री के निर्देशों पर प्राधिकरण की स्थिति में सुधार के तरीके सुझाने के लिए हिमुडा के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमुडा लैंड पूलिंग नीति अपनाने पर विचार कर रहा है। हिमुडा ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 156 करोड़ रुपये से 1731 बीघा भूमि खरीदी है और अब अधिक भूमि खरीदने के बजाय, राजस्व जुटाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति के अनुसार

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया है और कर्मचारियों ने अविलम्ब अपने सभी देय लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी, प्रदेश सरकार ने कई अन्य राज्यों के विपरीत यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को उनका वेतन और बकाया समय पर मिले।

राज्य एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से सम्बन्ध रखने वाले मुख्यमंत्री आम आदमी की कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता, आर. डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, रजनीश और सुभाशीष पांडा, सचिव देवेश कुमार, अमिताभ अवस्थी, डॉ. अजय शर्मा, अध्यक्ष सुद सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

रोजगार योग्यता कौशल पर प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग और क्वेस्ट एलायंस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क के साथ एक समझौता

संस्थानों के सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ट्रेनर को इस समझौते के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे आई.टी.आई. के लगभग 35,000 प्रशिक्षुओं को लाभ मिलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्ण व्यय क्वेस्ट एलायंस द्वारा वहन किया

किया जाए, विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरान्त यह प्रशिक्षक छात्रों को एक मिश्रित पद्धति का उपयोग करके रोजगार योग्यता कौशल पर प्रशिक्षण देंगे, जिसमें क्वेस्ट ऐप का भी उपयोग किया गया है।

क्वेस्ट ऐप के माध्यम से रोजगार कौशल, डिजिटल साक्षरता और प्रवाह, कार्यस्थल की तैयारी जैसे रचनात्मक समस्या समाधान और निर्णय लेने में डेटा उपयोग, कैरियर प्रबंधन कौशल, विकास की मानसिकता एवं प्रशिक्षुओं के लिए कैरियर यात्रा की पहचान करने और योजना बनाने की क्षमता में कौशल विकसित करने के लिए 90 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों की साझेदारी का रणनीतिक लक्ष्य कुशल कार्यबल की दुनिया में भारत के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं को महत्वपूर्ण कौशल से परिपूर्ण करना है।

उन्होंने बताया कि नए जारी किए गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टूलकिट, जिसमें अंग्रेजी संचार, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल, कक्षाओं में खेल-खेल में अन्य गतिविधियों के साथ-साथ सेल्फ लर्निंग डिजिटल एप्लिकेशन के माध्यम से काम करना इत्यादि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स विषय की समझ को आसान बनाएगी। प्रशिक्षण के बाद कैस्केड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण और गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री एक्सपोजे, छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण और शिक्षण सहायता साझा की जाएगी।



ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क एक्सेचर, सिस्को और जेपी मॉर्गन का एक सहयोगी प्रयास है और गैर-लाभकारी क्वेस्ट एलायंस द्वारा सुविधा प्राप्त है।

उन्होंने बताया कि समझौता ज्ञापन पर विवेक चंदेल, निदेशक, तकनीकी शिक्षा और वेणुगोपाल थिरुमलपाद, निदेशक क्वेस्ट एलायंस, बेंगलुरु ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सुनील वर्मा, संयुक्त निदेशक (टीई), संजय गुप्ता उप निदेशक, प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा निदेशालय से और एम. एस. महला कार्यक्रम समन्वयक, सुलभ कुमार एसोसिएट निदेशक और संजना बिनवाल कार्यक्रम अधिकारी क्वेस्ट एलायंस उपस्थित थे।

प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 138 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

जाएगा और राज्य कोष पर इसका कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10 मास्टर प्रशिक्षकों को पाठ्यक्रम का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर प्रशिक्षक क्वेस्ट एलायंस के सहयोग से सभी सरकारी आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पाठ्यक्रम के प्रभारी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम में वेबिनार, पठन सामग्री, वीडियो पाठ्यक्रम, असाइनमेंट आदि जैसे आभासी और भौतिक मॉडल के माध्यम से 50 घंटे के रोजगार योग्यता कौशल पाठ्यक्रम, नए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पाठ्यक्रम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लासेस को कैसे सुगम बनाया जाए और आईआईटी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम रोल आउट को कैसे व्यवस्थित

हिमुडा, इच्छुक निजी भूमि मालिकों की भूमि का अधिग्रहण किए बिना उनकी भूमि को विकसित कर उसका विपणन करेगी।

उन्होंने कहा कि शिमला, सोलन, धर्मशाला जैसे निकटतम प्रसिद्ध स्थानों की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए हिमुडा द्वारा विभिन्न स्थानों पर कॉलोनियां प्रस्तावित की हैं। उन्होंने अधिकारियों से और अधिक दक्षता के साथ कार्य करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हिमुडा को विशेष रूप से शिमला से सम्बन्धित विभिन्न कार्य सौंपे गये हैं और इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के लिए एक उचित कार्य प्रणाली विकसित करनी होगी।

उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमुडा द्वारा भूमि खरीद के दौरान कुछ अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी। हिमुडा राज्य में विभिन्न स्थानों पर अपनी भूमि के बड़े हिस्से को लीज पर देने के लिए उद्योग, बागवानी विभाग से सम्पर्क कर रहा है। उन्होंने हिमुडा को आवंटियों और अन्य हितधारकों को वन स्टॉप सिस्टम प्रदान करने और इसके लिए एक समर्पित नम्बर और व्हाट्स ऐप नम्बर आरम्भ करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय वर्मा सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

कामधेनु हितकारी मंच गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला बिलासपुर के कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल को सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति के रूप में गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। समिति को यह पुरस्कार भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की ओर से प्रदान किया जा

रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कामधेनु हितकारी मंच 5,445 सक्रिय कृषक सदस्यों के साथ प्रदेश की अग्रणी समिति है और इस समिति का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति वर्ग में देश के प्रतिष्ठित गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित होना समिति से जुड़े सभी किसानों के लिए सम्मान की बात है।

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिये फोक मीडिया कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क द्वारा प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों को

हुए।

आरती गुप्ता ने कहा कि आज समाज में बहुत बदलाव आए हैं, अनेक चुनौतियां हैं। हमें इन चुनौतियों को



फोक मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से फोक मीडिया पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ परिमहल शिमला में किया गया।

कार्यशाला के प्रथम दिन अतिरिक्त निदेशक आरती गुप्ता मुख्य अतिथि तथा संयुक्त निदेशक प्रदीप कंवर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित

अवसर में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फोक मीडिया जन-जन से जुड़ने का सशक्त माध्यम है। आप इस माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर-घर, गांव-गांव तक पहुंचाएं, दर्शकों से सुमधुर सम्पर्क व सम्बन्ध बनाएं ताकि आम जन न केवल योजनाओं के विषय में जानें बल्कि योजना विशेष के पात्र लाभार्थी अधिक से अधिक

योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें।

इसके उपरान्त, प्रदीप कंवर ने कहा कि हमारी नाटक की शैली लोक शैली पर आधारित हो तो लोग शीघ्र ही सरकार की योजनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन-जन तक सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए हमें स्वयं योजनाओं के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सांस्कृतिक दल विभाग से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यशाला के दौरान राज्य नाट्य दल व जिला नाट्य दल के कलाकारों ने नैमित्तिक कलाकारों के सहयोग से प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों पर तैयार किया गया समूह गान, नाटक व नशा निवारण पर आधारित समूह गीत भी प्रस्तुत किया।

लोक नाट्य कार्यशाला में विभाग द्वारा प्रदेश भर के अनुमोदित 62 दलों के मुखिया तथा विभिन्न जिलों में नियुक्त नाट्य निरीक्षक भाग ले रहे हैं।

राज्यपाल ने 31वीं सब जूनियर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 31वीं सब-जूनियर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने

राज्यपाल ने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अनुशासन सीखना चाहिए क्योंकि



कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना बनाए रखें तथा हार से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में तन व मन लगाकर खेलें। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स-स्पोर्ट्स मिट्टी से जुड़ा खेल है, जिसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स-स्पोर्ट्स को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा में देश भर की 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं।

खेल के मैदान के अनुभव जीवन में आगे बढ़ने का सबक बनते हैं। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों की प्रतिभा को निखरने का अवसर मिलता है।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टोक्यो पैरा-ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निषाद ने मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर खेलों के प्रति प्रोत्साहित होगी।

इससे पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित छठे राज्य वित्तयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांत राज्य है, जो अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है तथा यहां के निवासी मृदुभाषी एवं मिलनसार हैं। उन्होंने कहा कि ऊना की धरती ने अनेकों महान खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी में पद्मश्री चरणजीत सिंह व दीपक ठाकुर ऊना से ही हैं। अभी हाल ही में टोक्यो पैरा-ओलंपिक में निषाद कुमार ने भी रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि भी कहा जाता है क्योंकि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा ने जीता था।

प्रतियोगिता में 612 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लड़कों के वर्ग में पहला मैच गोवा व छत्तीसगढ़ की टीम के बीच खेला गया, जबकि लड़कियों के वर्ग में पहला मुकाबला कोल्हापुर तथा केरल के बीच हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया और उन्हें मैच के लिए शुभकामनाएं दी।

प्रदेश में 9 केंद्रों के माध्यम से दो लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद, 4000 से अधिक किसानों को 38 करोड़ रुपए का भुगतान

शिमला/शैल। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास से भारतीय खाद्य निगम ने धान खरीद को लेकर दो लाख क्विंटल का आंकड़ा पार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एफसीआई द्वारा 9 खरीद केंद्रों पर कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। विशेष बात यह है कि प्रदेश के किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान भी 24 घंटे के भीतर ही करवाया जा रहा है। प्रदेश के करीब चार हजार किसानों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाते हुए उनके खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए से

अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि गत 15 अक्टूबर, 2021 से धान खरीद का कार्य सिरमौर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला के विभिन्न खरीद केंद्रों पर प्रारंभ किया गया है। सिरमौर जिला में हरिपुर-टोहाना, काला अंब व पीपलीवाला, ऊना जिला में टकराला मंडी और टाहलीवाल, कांगड़ा जिला में फतेहपुर मंडी व इंदौरा स्थित त्योराह तथा सोलन जिला में नालागढ़ मंडी और मालपुर में यह खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इन केंद्रों के माध्यम से 24 नवम्बर, 2021 तक लगभग 2,14,311.95 क्विंटल

धान की खरीद की जा चुकी है और इससे लगभग 4,474 किसानों को लाभ पहुंचा है। आंकड़ों के अनुसार सिरमौर जिला में अभी तक लगभग 1,01,808.78 क्विंटल, ऊना जिला में लगभग 19,612.16 क्विंटल, कांगड़ा जिला में लगभग 51,685.50 क्विंटल और सोलन जिला में लगभग 41,205.52 क्विंटल धान की खरीद की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार व कृषि मंत्री के निर्देशों के अनुरूप कृषि उपज विपणन समिति ने खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए किसानों की उपज की खरीद और उन्हें समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया है।

राज्यपाल ने माता चिंतपूर्णी मंदिर में टेका माथा

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेका और प्रदेशवासियों की

की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने कहा कि चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं



सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर माता चिंतपूर्णी की संध्या आरती में भी शामिल हुए और मां का आशीर्वाद लिया।

उन्होंने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्था है तथा यहां विश्व भर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश सरकार चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रही है।

अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा ने इस अवसर पर राज्यपाल को माता चिंतपूर्णी की चुनरी तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यहां ट्रेन से मां चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदान

तथा प्रदेश सरकार सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन से चिंतपूर्णी मंदिर के लिए एक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर कुछ कार्य होना बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयासरत है, जिससे चिंतपूर्णी मार्ग रेलवे स्टेशन से चिंतपूर्णी मंदिर की दूरी 12 कि.मी. रह जाएगी। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द इस प्रस्तावित सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे श्रद्धालु लाभान्वित होंगे।

राज्यपाल ने चिंतपूर्णी में अपने पारिवारिक मित्र मलकीयत सिंह से भी घर जाकर मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर विधायक चिंतपूर्णी बलबीर सिंह, उप-मंडलाधिकारी मनेश कुमार यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

'धामी गोलीकाण्ड' घटना पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में व्याख्यान

शिमला/शैल। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (एडवांस्ड स्टडी) में भारत की आजादी के संघर्ष में हिमाचल के योगदान को उजागर करते हुए 'धामी गोलीकाण्ड' घटना के आलोक में

निकाय के रूप में हिमालय रियासती प्रजामंडल का गठन हुआ। 16 जुलाई 1939 को हुई धामी गोलीकाण्ड घटना हिमाचल की पहाड़ियों में स्वतंत्रता की ओर हमारे देश की यात्रा को चिह्नित



'शिमला, द हिल स्टेट्स एंड द फायरिंग एट धामी' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। यह व्याख्यान शिमला के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार एवं पत्रकार राजा भसीन द्वारा प्रस्तुत किया।

मुख्य वक्ता राजा भसीन ने बताया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के लिए शिमला एक सुरक्षा कवच की भांति था। शहर में रहने वाले भारतीयों की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से औपनिवेशिक व्यवस्था पर निर्भर थी मगर फिर कुछ लोग इस व्यवस्था के अन्याय को महसूस कर रहे थे और उसके विरुद्ध संघर्ष भी कर रहे थे। इस अन्याय और शोषण व्यवस्था का प्रभाव स्थानीय पहाड़ी शासकों पर पड़ा, जिन्हें ब्रिटिशराज के उपकरण के रूप में माना जाता था। अन्याय और शोषण से मुक्ति पाने के लिए 1 जून 1939 को एक राष्ट्रवादी

करने वाली काली घटनाओं में से एक बहुत ही घृणित घटना है जो सत्ता और विशेषाधिकार, स्थानीय लोगों की मजबूरियों तथा ग्रामीण किसानों के बीच संघर्ष की पीड़ादायक दस्तान को बयान करती

है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चमन लाल गुप्त ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी युक्त व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए राजा भसीन का आभार माना। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश काल से पूर्व तथा ब्रिटिश कालीन शिमला की सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में संस्थान की भागीदारी को भी रेखांकित किया। संस्थान के सचिव प्रेम चंद ने मुख्य वक्ता तथा उपस्थित सभासदों का धन्यवाद किया। संस्थान के सभी अध्यक्षता, आईयूसी सह-अध्येता, आवासी विद्वान, अधिकारी और कर्मचारी इस व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऑफलाइन के साथ-साथ इस कार्यक्रम को सिस्को वेबएक्स तथा संस्थान के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित किया गया।

मोदी के बाद नड्डा ने भी कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 72,000 करोड़ दिये हैं

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी को आभासी संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार ने वित्त आयोग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए दिये हैं। जबकि उनसे पहले यह राशि 20,000 करोड़ तक ही रही है। नड्डा के मुताबिक यह बढ़ा हुआ आबंटन यह दिखाता है कि मोदी हिमाचल को कितनी अहमियत देते हैं। नड्डा से पहले मण्डी की जनसभा में स्वयं मोदी भी इस आंकड़े का जिक्र कर चुके हैं। उस समय इस आंकड़े पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वह एक चुनावी जनसभा में दिया भाषण था। लेकिन अब जब नड्डा ने यह आंकड़ा प्रदेश कार्यकारिणी में रखते हुए यह अपेक्षा की है कि वह इसे प्रदेश के हर आदमी तक पहुंचाये। नड्डा ने अपने संबोधन में उपचुनाव में मिली हार और 2022 तक का चुनाव भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा इस पर सीधे और स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। केवल

❖ केंद्र से 72,000 मिलने के बावजूद लिया गया 70,000 करोड़ का ऋण



सरकार को मजबूत करने का आग्रह किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने संबोधन में यही संदेश देना पड़ेगा।

नड्डा ने अपने संबोधन में उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाओं की याद प्रदेश के लोगों को दिलाई है। लेकिन वह यह बताना भूल गये कि इस योजना के तहत 67: लाभार्थी आज रीफिल नहं करवा पाये हैं। प्रदेश में घोषित हर योजना का व्यवहारिक पक्ष ऐसा ही है। अनुसूचित जाति के एक सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया है कि उनके लिए

आबंटित बजट का केवल 7 : ही यह सरकार खर्च रही है। इस आशय का ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया है। परंतु अभी तक इस आरोप का जवाब तक नहीं आया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि केंद्र ने प्रदेश को 72 हजार करोड़ दिये हैं तो राज्य सरकार ने उसका उपयोग कैसे किया है। यह जानना प्रदेश की जनता का हक हो जाता है।

स्मरणीय है कि मोदी सरकार ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभाली थी। उसके बाद इस सरकार में 2017 में

अगले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तब तक 2012 में आयी वित्त आयोग की सिफारिशें ही अमल में चल रही और इन सिफारिशों में प्रदेश के लिए 20 हजार करोड़ का ही आबंटन हो पाया था। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को 72 हजार करोड़ देने का मौका 2017 के आयोग की सिफारिशों में ही आता है। 72 हजार करोड़ का आंकड़ा दूसरी बार सामने आया है। वह भी पहले प्रधानमंत्री द्वारा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दोहराया गया है। जब इस स्तर के लोग यह कहें तो इस

पर यकीन किया जाना चाहिये। लेकिन 2017 से लेकर अब तक प्रदेश सरकार 70000 करोड़ का तो ऋण ही ले चुकी है। हर वर्ष बजट के बाद टैक्स और अन्य शुल्क सरकार बढ़ाती आ रही है। जबकि जनता को यह परोसा जाता है कि सरकार कर मुक्त बजट लायी है। रिकॉर्ड बताता है कि हर वर्ष कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा करीब डेढ़ लाख करोड़ खर्च कर दिये जाने के बाद भी यदि पुलिस जैसे विभाग को भी अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का अपरोक्ष सहारा लेना पड़े तो यह सबके लिये चिंता और चिंतन का विषय हो जाता है। क्योंकि केंद्र द्वारा इतनी खुली सहायता के बाद भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़े तो इस पर जनता को सवाल पूछने का हक हो जाता है। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि यह आवंटन भी 69 राष्ट्रीय राजमार्गों जैसा ही है या सही में इतना पैसा प्रदेश को मिला है। क्योंकि 2022 में तो अगले वित्त आयोग की सिफारिशें आ जायेंगी।

स्वर्ण आयोग की राजनीति में धिंती कांग्रेस और भाजपा

शिमला/शैल। पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी शिमला में कुछ स्वर्ण संगठनों ने स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर 800 किलोमीटर की हरिद्वार तक पदयात्रा करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही शिमला में एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा भी निकाली है। इस शव यात्रा का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों ने विरोध किया है। इस शव यात्रा को संविधान का अपमान करार देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका दायर करने की भी बात की है। इस शव यात्रा के विरोध में हर जिले में इन वर्गों का नेतृत्व जिलाधीशों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने की रणनीति पर आ गया है। जो स्वर्ण संगठन स्वर्ण आयोग गठित किए जाने की मांग कर रहे हैं उनकी मांगों में यह भी शामिल है कि आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं वरन आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्रीमी लेयर के मानक का कड़ाई से पालन होना चाहिए। यदि इन मांगों को

❖ क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख करना क्या सही है
❖ क्या स्वर्ण आयोग के पक्षधर विधानसभा में क्रीमी लेयर पर चर्चा करेंगे

ध्यान से देखा समझा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह मांग राजनीति से प्रेरित और अंतः विरोधी है। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान देश की पहली संसद द्वारा गठित काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें आने पर कर दिया गया था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने पर गठित हुए मंडल आयोग की सिफारिशें स्व.वी.पी. सिंह की सरकार के कार्यकाल में लागू करने से अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 27% का आरक्षण लाभ मिल गया था। इसी सरकार में इस आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ। वीपी सिंह की सरकार इसकी बलि चढ़ गई और आरक्षण का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आरक्षण का आधार आर्थिक कर दिया। आर्थिक संपन्नता के लिए क्रीमी लेयर को मानक बना दिया। उस समय जो क्रीमी

लेयर की सीमा एक लाख तय की गई थी वह आज मोदी सरकार में आठ लाख हो गई है। मोदी सरकार ही क्रीमी लेयर की सीमा दो बार बढ़ा चुकी है। यह है आज की व्यवहारिक सच्चाई। हो सकता है स्वर्ण आयोग के गठन की मांग करने वाले सभी लोगों को इस स्थिति का ज्ञान ही ना हो।

जब सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही हर तरह के आरक्षण का आधार आर्थिक करके क्रीमी लेयर का मानक तय कर दिया है तब आरक्षण के विरोध का आधार कहाँ बनता है। या तो यह मांग की जाये कि किसी भी तरहका आरक्षण हो ही नहीं। चाहे कोई अमीर है या गरीब है किसी के लिए भी आरक्षण होना ही नहीं चाहिये। गरीबों के लिए किसी भी तरह की कोई योजना होनी ही नहीं चाहिये। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ही खत्म कर दी जानी चाहिये। क्या आज स्वर्ण आयोग के गठन की मांग करने वाला कोई भी

राजनेता या राजनीतिक दल यह कहने का साहस कर सकता है कि सभी तरह का आरक्षण बंद होना चाहिये। वी.पी. सिंह सरकार के समय में जब मंडल बनाम कमंडल हुआ था तो उस समय किस विचारधारा के लोगों ने आरक्षण का विरोध किया था। अब जब से मोदी सरकार आयी है तब से कई राज्यों में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुये हैं। हर आंदोलन में यही मांग उठी है कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका समाप्त करो। संघ प्रमुख मोहन भागवत तक आरक्षण पर बयान दे चुके हैं। लेकिन इसी सबके साथ जब भी इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था दी तो मोदी सरकार ने संसद में शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया है।

इस दौरान हिमाचल ही एक ऐसा राज्य रहा है आरक्षण को लेकर कोई आंदोलन नहीं उठा है। अब जयराम सरकार के अंतिम वर्ष में

आरक्षण पर स्वर्ण आयोग की मांग के माध्यम से एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि यह मुद्दा भी मुख्यमंत्री के उस बयान का परिणाम है जिसमें उन्होंने कहा की स्वर्ण जातियों के हितों की रक्षा के लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान में कांग्रेस के भी विक्रमादित्य सिंह जैसे कई विधायक पार्टी बन गये हैं। सभी स्वर्ण आयोग गठित करने के पक्षधर बन गये हैं। क्या यह लोग विधानसभा के इस सत्र में इस पर चर्चा करेंगे की क्रीमी लेयर में आठ लाख का मानक कैसे तय हुआ है। आठ लाख की वार्षिक आय का अर्थ है करीब 67000 प्रति माह। यदि 67 हजार प्रतिमाह की आय वाला व्यक्ति भी आरक्षण का हकदार है तो सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि इस मानक में प्रदेश के कितने लोग आ जाते हैं। स्वर्ण आयोग की मांग करने वालों को भी इस मानक पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिये। जब आरक्षण आर्थिक आधार पर मांगा जा रहा है तो फिर और मुद्दा ही क्या बचता है।